



एएफआर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या - 4204 वर्ष 2025

राम आश्रय

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजय शंकर, त्रिवेणी शंकर

प्रतिवादियों के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आर एस दूबे, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, सविता दूबे, उमेश कुमार प्रसाद

सुरक्षित : 2.12.2025

प्रदत्त : 22.1.2026

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र कुमार राय

1. श्री त्रिवेणी शंकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता सुश्री गरिमा जायसवाल, याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता ने की, श्री आर.एस. दुबे, प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता, श्री आशुतोष कुमार राय, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, और श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, प्रतिवादी संख्या 4 / ग्राम पंचायत के विद्वान अधिवक्ता, की दलीलें सुनी गईं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ग्राम - शाहपुर, परगना - खरीद, तहसील - बांसडीह, जिला-बलिया में स्थित भूखंडों का चक धारक संख्या 227-बा है। याचिकाकर्ता की मूल जोत भूखंड संख्या 16/2 क्षेत्रफल 0.170 हेक्टेयर, 169 क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, 233/1 क्षेत्रफल 0.261 हेक्टेयर, 233/2 क्षेत्रफल 0.010 हेक्टेयर, 286 क्षेत्रफल 0.134 हेक्टेयर, 289 क्षेत्रफल 0.198 हेक्टेयर है; कुल 6 भूखंड जिनका क्षेत्रफल 0.898 हेक्टेयर है, जैसा कि रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 5 में उल्लेखित है। यूपी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 (जिसे इसके बाद 'यू0पी0सी0एच0 अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 9-ए (2) के तहत चकबंदी अधिकारी ने राम सुरेश का हिस्सा 1/4, रामाश्रय का 1/4, शिव शंकर का 1/4 और राजाराम का 1/4 निर्धारित किया। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दो चक प्रस्तावित किए गए। पहला चक याचिकाकर्ता को भूखंड संख्या 288 एम और 289 एम पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तावित किया गया, और दूसरा चक याचिकाकर्ता को भूखंड संख्या 233 एम, 233 एम, 233 एम पर प्रस्तावित किया गया; कुल 5 भूखंड जिनका क्षेत्रफल 0.203 हेक्टेयर है। सहायक चकबंदी अधिकारी के इस प्रस्ताव के विरुद्ध, प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम द्वारा चक संबंधी आपत्ति दायर की गई, जिसका निस्तारण चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 10.03.2008 के आदेश द्वारा किया, जिससे याचिकाकर्ता के चक में फेरबदल हो गया। चकबंदी अधिकारी के 10.3.2008 के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने यू0पी0सी0एच0 अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी के सामने एक अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि उसे भूखंड संख्या 386 और 389 पर चक आवंटित किया जाना चाहिए। चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी ने 28.5.2008 के आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को मंजूर कर लिया और याचिकाकर्ता को भूखंड संख्या 15एम, 16एम, 17एम पर चक आवंटित किया, और प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम को भूखंड संख्या 288एम, 289एम, 233एम पर चक आवंटित किया गया। 28.5.2008 के अपीलीय आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम ने एक चक पुनरीक्षण दायर किया, जिसमें उसने अपने मूल भूखंड संख्या 16/2 क्षेत्रफल 0.42 दशमलव पर चक के आवंटन की मांग की। प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम द्वारा दायर किया गया उपरोक्त चक पुनरीक्षण लगभग 16 वर्षों तक लंबित रहा। उपरोक्त चक पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, राम सुरेश का निधन हो गया, और मृतक राम सुरेश के कानूनी वारिसों का भी निधन हो गया; साथ ही, पुनरीक्षण में शामिल कुछ अन्य व्यक्तियों का भी निधन हो गया, लेकिन लंबित चक पुनरीक्षण में कोई प्रतिस्थापन आवेदन दायर नहीं किया गया। उप निदेशक, चकबंदी ने 15.7.2025 के आदेश के ज़रिए पुनरीक्षण को मंजूर कर लिया और याचिकाकर्ता के चक में बदलाव करते हुए, उसके चक से भूखंड संख्या 15एम, 16एम और 17एम को हटा दिया, और उन्हें प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम को आवंटित कर दिया। अतः, निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:-

"(a) उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा उप निदेशक, चकबंदी, बलिया द्वारा पारित दिनांक 15.7.2025 के आक्षेपित आदेश (संलग्नक संख्या 1) को रद्द किया जाए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस न्यायालय ने 17.10.2025 को इस मामले पर सुनवाई की और दिनांक 15.7.2025 के आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। दिनांक 17.10.2025 का आदेश इस प्रकार है:-

"1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिन के दौरान रिट याचिका के प्रार्थना खंड में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिवेणी शंकर, प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. दुबे, राज्य - प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी - ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना गया।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षण स्तर पर, याचिकाकर्ता की तुलनात्मक कठिनाई पर उचित तरीके से विचार किए बिना, याचिकाकर्ता के चक को प्रभावित किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

4. दूसरी ओर, निजी प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चकबंदी उप निदेशक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जिसमें दोनों पक्षों को उचित तरीके से समायोजित किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस मामले का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए, क्योंकि आक्षेपित आदेश के तहत केवल प्रतिवादी संख्या 5 का चक प्रभावित हुआ है, जबकि अन्य निजी प्रतिवादियों का चक इस आदेश से प्रभावित नहीं हुआ है।

5. यह मामला विचारणीय है।

6. प्रतिवादी संख्या 5 वह आक्षेपित प्रतिवादी है, जिसकी चक आक्षेपित आदेश के तहत प्रभावित हुई है; अतः, शेष निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने पर अगली सुनवाई की तारीख को विचार किया जाएगा।

7. प्रतिवादी संख्या 5 एक सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा। इसके एक सप्ताह बाद याचिकाकर्ता अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करेगा।

8. इस मामले को 4.11.2025 को दोपहर 12.00 बजे 'ताज़ा मामले' के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इस न्यायालय के अगले आदेशों तक, उप-निदेशक, चकबंदी द्वारा पारित

दिनांक 15.7.2025 के आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश का प्रभाव और क्रियान्वयन स्थगित रहेगा; साथ ही, रिट याचिका के पक्षकार आक्षेपित भूखंड की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।”

4. दिनांक 17.10.2025 के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से एक प्रति-शपथ पत्र दायर किया गया है, और याचिकाकर्ता ने अपना प्रत्युत्तर शपथ पत्र दायर किया है।

5. अन्य निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 के चक को आक्षेपित आदेशों के तहत समायोजित किया गया है; यह बात आक्षेपित आदेशों के समर्थन में तैयार की गई अनुसूची से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी ने वर्ष 2008 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर चक अपील का निर्णय सही ढंग से किया था। उन्होंने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वर्ष 2008 में दायर चक पुनरीक्षण याचिका 16 वर्षों से अधिक समय तक लंबित रही, और इस दौरान कई पक्षकारों का निधन हो गया; परंतु, मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसों को पक्षकार बनाए बिना ही, उप-निदेशक, चकबंदी ने आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर चक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया गया, जिससे वर्ष 2008 में अपीलीय न्यायालय द्वारा किए गए चक आवंटन की व्यवस्था भंग हो गई। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि वर्ष 2008 में चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किए गए आवंटन के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम ने उसे आवंटित भूमि की प्रकृति को बदल दिया था; उसने ईंटों के निर्माण हेतु भूमि से मिट्टी निकाल ली, जिसके परिणामस्वरूप वह भूखंड खेती के अयोग्य हो गया है। उन्होंने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता को ऐसे भूखंड पर चक आवंटित नहीं किया जा सकता, जिसे प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम ने खेती के अयोग्य बना दिया है। उन्होंने निवेदन किया कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किए गए आवंटन को यथावत रखा जाना चाहिए, और आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर चक अपील को अवैध और मनमाने ढंग से स्वीकार किया गया था; अतः, चक पुनरीक्षण की कार्यवाही में, उप-निदेशक, चकबंदी ने यू0पी0सी0एच0 अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पक्षकारों के चकों का समायोजन सही ढंग से किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 - राजाराम ने कभी भी मिट्टी नहीं बेची है, जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण पर फैसला लेने में देरी हुई है, क्योंकि चकबंदी आयुक्त ने 22.12.2008 के आदेश के ज़रिए चकबंदी की कार्यवाही रद्द कर दी थी, लेकिन रद्द करने के उस आदेश पर इस न्यायालय ने 21.5.2009 के आदेश के ज़रिए रोक लगा दी थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 5, भूखंड संख्या 16एम का मूल चक-धारक है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 को उसी पर समायोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि चकबंदी उप-निदेशक द्वारा पारित आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 को, यू0पी0सी0एच0 अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रावधानों के अनुसार, जहाँ तक संभव हो, उनके मूल भूखंडों पर समायोजित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर चक अपील में, याचिकाकर्ता को भूखंड संख्या 15एम, 16एम, 17एम पर समायोजित किया गया था और प्रतिवादी संख्या 5 को भूखंड संख्या 288, 289, 233 पर समायोजित किया गया था; लेकिन लगभग 16 साल से भी अधिक समय बाद पारित आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश के तहत, याचिकाकर्ता को भूखंड संख्या 289, 233, 288 पर चक आवंटित किया गया है और प्रतिवादी संख्या 5 को भूखंड संख्या 15एम, 16एम और 17एम पर चक आवंटित किया गया है।

10. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यू0पी0सी0एच0 अधिनियम की धारा 19 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ तक संभव हो, काश्तकार को उसके मूल भूखंड पर ही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चक आवंटित किया जाना चाहिए; यद्यपि, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक काश्तकार को उसका हर चक उसके मूल भूखंड पर ही आवंटित किया जाए। इस मामले में, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा लगभग 16 साल पहले जो आवंटन किया गया था, वह लगभग 16 साल तक लागू रहा; इसलिए, उसमें आगे जो भी बदलाव किए गए 16 वर्षों के बाद उप-निदेशक, चकबंदी द्वारा लिया गया निर्णय न्याय के हित में नहीं है।

11. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने भूखंड संख्या 233, 288 और 289 को खेती के अयोग्य बना दिया है, हालाँकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा भूखंड को खेती के लिए अनुपयुक्त बनाने के संबंध में दिए गए तर्क पर आपत्ति जताई है। लेकिन तथ्य यह है कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा लगभग 16 वर्ष पूर्व किया गया आवंटन, चकबंदी उप निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना बदल दिया गया है, जो यू0पी0सी0एच0 अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण का निर्णय लेने के लिए एक अनिवार्य मानदंड है।

12. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि इतनी लंबी अवधि के बाद, वर्ष 2008 में चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किए गए आवंटन के विरुद्ध चक पुनरीक्षण का निर्णय नए सिरे से करने के लिए मामले को चकबंदी उप निदेशक के पास वापस भेजना न्याय के हित में नहीं है; बल्कि इस मामले में आवंटन को एक ही स्तर पर अंतिम रूप देना ही उचित है।

13. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 / चकबंदी उप निदेशक द्वारा दिनांक 15.7.2025 को पारित आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश रद्द किए जाने योग्य है, और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है।

14. रिट याचिका स्वीकार की जाती है, और चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 28.5.2008 को पारित आदेश को यथावत बरकरार रखा जाता है।

15. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

जनवरी 22, 2026

पीएस

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।